किसानों की त्वरित सहायता पर फोकस : शिवराज

तत्काल जरूरतों, बीमा दावों की प्रक्रिया और राहत व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई

नई दिल्ली, 20 मार्च. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में देश के कृषि क्षेत्र की समग्र स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की.

बैठक में हाल के दिनों में कई राज्यों में हुई अतिवृष्टि, तेज बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण किसानों को हुए संभावित नुकसान, उनकी तत्काल जरूरतों, बीमा दावों की प्रक्रिया तथा राहत व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई. समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि हमारा फोकस केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि फसल-क्षति के वैज्ञानिक आकलन, बीमे के सही क्लेम और किसानों की त्वरित सहायता पर भी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई, जब कई राज्यों में मौसम की अनिश्चितता, फसल-क्षति की आशंका और किसानों की त्वरित सहायता की आवश्यकता प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, ताकि नीति, राहत और मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं की तीनों स्तरों पर समन्वित रूप से काम किया जा सके.

प्रतिकूल मौसम, मौसम पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन- बैठक में मौसम पूर्वानुमान और फसलों की ताजा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई, ताकि आने वाले दिनों में संभावित मौसम जोखिमों के अनुसार तैयारी की जा सके. श्री चौहान ने कहा कि कृषि विभाग, राज्यों और संबद्ध संस्थाओं को मिलकर ऐसी कार्ययोजना बनानी चाहिए, जिससे किसान को समय पर सलाह, सहायता और सुरक्षा मिले. उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र का लक्ष्य केवल उत्पादन नहीं, बल्कि किसान की सुरक्षा, आय स्थिरता और समय पर सहायता होना चाहिए, और फसल-स्थिति, मौसमीय जोखिम, प्रोक्योरमेंट रेडीनेस तथा राहत तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है.

श्री चौहान ने बताया कि आने वाले दिनों में गेहूं और धान की सरकारी खरीद प्रारंभ होने जा रही है और इस बार रबी फसलों का उत्पादन बंपर रहा है, जिससे देश के पास गेहूं, धान और चावल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि हम गेहूं-धान भी खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ दलहन की फसलों पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है.

फसल-क्षति का वैज्ञानिक आकलन और बीमा क्लेम पर विशेष जोर

श्री चौहान ने बैठक में उपस्थित केंद्रीय कृषि सचिव, कृषि आयुक्त तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को जहां भी सहायता की आवश्यकता हो, वहां राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र क्रॉप कटिंग प्रयोग, नुकसान का वैज्ञानिक आकलन और त्वरित राहत सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में तेज बारिश, ओलावृष्टि या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थितियों से नुकसान हुआ है, वहां फील्ड स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है, ताकि किसी भी किसान को राहत के लिए इंतजार न करना पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि मौसम विभाग ने आगे दो और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई है, इसीलिए किसानों को क्या सलाह दी जाए, इस पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

5% होम इंटरनेट से जियो को मिल रही रफ्तार

विश्लेषकों ने जियो की रणनीति को बताया मजबूत

नई दिल्ली, 20 मार्च. ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के अनुसार भारतीय टेलीकॉम बाजार में रिलायंस जियो की बढ़त और मजबूत हुई है. फर्म की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी मोबाइल सेवाओं के साथ-साथ होम ब्रॉडबैंड और 5त्न फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट में भी आगे बनी हुई है.

जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक जनवरी 2026 की सब्सक्राइबर रिपोर्ट के रुझानों से पता चलता है कि जियो ने महीने के दौरान सबसे ज्यादा नए मोबाइल ग्राहक जोड़े. कंपनी से करीब 16 लाख नेट वायरलेस यूजर जुड़े. वहीं भारती एयरटे ने लगभग 12 लाख ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया के करीब 7 लाख ग्राहक घटे. ये आंकड़े भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के डेटा पर आधारित हैं. जेएम फाइनेंशियल के अनुसार जियो 41 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी वायरलेस कंपनी बनी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया कि एयरटेल दूसरे नंबर पर बनी हुई है, लेकिन वोडाफोन आइडिया लगातार पिछड़ रही है.होम ब्रॉडबैंड कारोबार में भी जियो की बढ़त जारी रही.

> विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे जियोएयरफाइबर की लगातार मजबूत होती मांग है. कहा गया कि 5प्रतिशत फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट बाजार यानी एयरफाइबर मार्केट में जियो की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से ज्यादा है, जिससे कंपनी को शुरुआती बढ़त मिली है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यही सेगमेंट टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है. जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि फाइबर और वायरलेस ब्रॉडबैंड दोनों पर एक साथ विस्तार करने की जियो की रणनीति प्रतिस्पर्धियों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है और इससे कंपनी की बाजार स्थिति मजबूत रह सकती है.

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बंद खनन ब्लॉकों पर उठाये सवाल

नई दिल्ली, 20 मार्च. खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पिछले 10 साल में आवंटित 85 प्रतिशत खनन ब्लॉक के बंद होने पर चिंता जतायी है.

अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पिछले 10 वर्षों में नीलाम किये गये करीब 85 प्रतिशत खनन ब्लॉक आज भी चालू नहीं हो पाये हैं. इस दौरान कुल 592 ब्लॉक नीलाम किये गये जिनमें से केवल 82 ही उत्पादन कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच उन्होंने ऊर्जा और खनिज सुरक्षा पर जोर दिया और नीलामी के बाद खदानों को जल्द चालू करने की प्रक्रिया तेज करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण में तकनीक आधारित सीधे भुगतान की व्यवस्था, मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रीमियम की सीमा 60 प्रतिशत तक तय करना जरूरी है.

अग्रवाल ने कहा कि देश के करीब 400 अरब डॉलर के आयात बिल में से लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों के आयात पर खर्च होता है. इससे देश में रोजगार सृजन की संभावनाएं कम हो रही हैं और नौकरियां विदेशों में पैदा हो रही हैं.

आठ दिन में सोना-चांदी में भारी उतार-चढ़ाव

1.47 लाख रुपए पर पहुंचा सोना

2.34 लाख रुपए पर आई चांदी

नई दिल्ली, 20 मार्च. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार में दिखाई दे रहा है. शुक्रवार, 20 मार्च को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी ने तेज उछाल लिया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 549 घटकर 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया.वहीं, चांदी 3,727 की तेजी के साथ 2.34 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई. हालांकि पिछले कुछ दिनों में सोना

और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है.विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्पों से हटकर नकदी की ओर बढ़ रहा है. इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ा है.इसके अलावा महंगे होते कच्चे तेल, शेयर बाजार में गिरावट और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने भी इस उतार-चढ़ाव को तेज कर दिया है.ऐसे माहौल में निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है. सर्राफा बाजार में इस समय असामान्य उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जहां एक तरफ सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं चांदी लगातार मजबूत होती नजर आ रही है.20 मार्च को सोना 549 सस्ता होकर 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3,727 महंगी होकर 2.34 लाख प्रति किलो हो गई.यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है.विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है.

> पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख के ऑल टाइम हाई पर था, जो अब करीब 28,000 सस्ता हो चुका है.वहीं चांदी 3.86 लाख के उच्चतम स्तर से गिरकर अब काफी नीचे आ चुकी है, लेकिन हालिया तेजी संकेत देती है कि इसमें फिर से मजबूती आ सकती है.

एनटीपीसी-ऑक्टोपस एनर्जी में स्वच्छ ऊर्जा करार

नई दिल्ली, 20 मार्च.सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल ऊर्जा प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में अग्रणी ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है.

इस समझौते का उद्देश्य बिजली वितरण और खुदरा कारोबार, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना, डिजिटल ऊर्जा प्लेटफॉर्म, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की पहचान, मूल्यांकन और क्रियान्वयन करना है.एनटीपीसी की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजधानी में चल रहे भारत विद्युत शिखर सम्मेलन- 2026 के पहले दिन यह करार हुआ.विद्युत उद्योग पर यशोभूमि में आयोजित यह सम्मेलन और प्रदर्शनी 19 से 22 मार्च तक चलेगी.इसका आयोजन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है.हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पंकज अग्रवाल, मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष सिंह, एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गुरुदीप सिंह और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम की सीईओ रेनू नारंग उपस्थित थीं.

दिल्ली में सूक्ष्म नाट्य महोत्सव का भव्य आयोजन

थेस्पिस सीजन 5 में 31 नाटकों की शानदार प्रस्तुति

नई दिल्ली, 20 मार्च. वृक्ष थिएटर, जो नई दिल्ली स्थित एक थिएटर समूह है और जिसकी स्थापना 16 अगस्त 2015 को केरल क्लब में मानवता के लिए कला के आदर्श वाक्य के साथ हुई थी, ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को एलटीजी सभागार, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय सूक्ष्म नाटक महोत्सव, थेस्पिस सीजन 5 का सफलतापूर्वक आयोजन किया.

यह महोत्सव भारत रंग महोत्सव 2026 के अंतर्गत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था. राष्ट्रीय सूक्ष्म नाटक महोत्सव की शुरुआत वृक्ष थिएटर द्वारा पहली बार 2017 में की गई थी और इसे भारत का पहला विशिष्ट सूक्ष्म नाटक महोत्सव माना जाता है. इस महोत्सव का नाम इकारिया के थेस्पिस के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रंगमंच के इतिहास में पहला अभिनेता माना जाता है. इस महोत्सव का संचालन प्रख्यात रंगमंच कलाकार और निर्देशक डॉ. अभिलाष पिल्लई के निर्देशन में किया गया.

महोत्सव के पांचवें संस्करण में 31 सूक्ष्म नाटक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम अवधि 10 मिनट थी.देश भर से आए 600 से अधिक कलाकारों और तकनीशियनों ने 12 भारतीय भाषाओं में प्रस्तुतियां दीं.

मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या125 करोड़ के पार

नई दिल्ली, 20 मार्च. देश में मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या जनवरी में 0.54 प्रतिशत बढ़कर 125 करोड़ के पार पहुंच गयी.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी को मोबाइल देश में 125.09 करोड़ सब्सक्राइबर थे. डुदिसंबर के अंत में यह संख्या 124.42 करोड़ दर्ज की गयी थी. शहरी क्षेत्रों में सब्सक्राइबरों की संख्या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 71.71 करोड़ हो गयी.ग्रामीण शहरों में मासिक 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह संख्या 53.38 करोड़ दर्ज की गयी. मोबाइल सब्सक्राइबरों के मामलें में रिलायंस जिओ की बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक 39.29 प्रतिशत रही.इसके बाद क्रमश: एयरटेल (37.40 प्रतिशत), वोडाफोन आइडिया (15.86 प्रतिशत) और बीएसएनएल (7.44 प्रतिशत) का स्थान रहा.जनवरी में शुद्ध रूप से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में 66,97,762 का इजाफा हुआ.

शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 326 अंक मजबूत

मुंबई, 20 मार्च. पिछले कारोबारी दिवस की बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में कम कीमतों पर हुई लिवाली से प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 325.72 अंक (0.44 प्रतिशत) की बढ़त में 74,532.96 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 112.35 अंक यानी 0.49 प्रतिशत ऊपर 23,114.50 अंक पर पहुंच गया. बाजार में भारी बिकवाली देखी गयी थी और दोनों सूचकांक सवा तीन प्रतिशत के करीब टूटे थे. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 1,079 अंक चढ़ गया था, लेकिन बाद में इसकी तेजी सीमित रह गयी. मझौली और छोटी कंपनियों में भी आज तेजी रही.

> निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.74 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.09 प्रतिशत चढ़ा. आईटी, सरकारी बैंकों, फार्मा, धातु, स्वास्थ्य और ऑटो सेक्टरों में अच्छी मजबूती रही. बैंकिंग, निजी बैंक, रियलटी और मीडिया सेक्टरों के सूचकांक गिर गये. सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील और टेक महिंद्रा के शेयर तीन प्रतिशत से ज्यादा चढ़े. इंफोसिस, ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर दो से तीन प्रतिशत की बीच मजबूत हुए.

समाचार विशेष

केरलम चुनाव में तीन मोर्चों के बीच दिलचस्प मुकाबला

क्या स्थानीय निकाय चुनाव तय करेंगे सत्ता का समीकरण?

तिरुवनंतपुरम. केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भी राजनीतिक मुकाबला तीन मुख्य मोर्चों के बीच रहने की संभावना है. सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ), जिसे सीपीआई (एम) नेतृत्व दे रही है, विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है.

केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं. 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटें जीतीं, कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को 41 सीटें मिलीं और भाजपा कोई सीट नहीं जीत पाई. 2016 में पार्टी ने पहली बार एक सीट जीती थी.

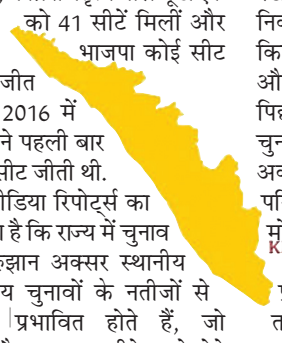

मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि राज्य में चुनाव का रुझान अक्सर स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से प्रभावित होते हैं, जो आमतौर पर कुछ महीने पहले होते हैं. अगर यह पैटर्न इस बार भी जारी रहता है, तो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ आगे रहने की संभावना रखती है. उन्होंने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे एलडीएफ दूसरी और भाजपा तीसरी स्थिति में रही. पिछले दो दशकों में विधानसभा चुनाव में तीनों मोर्चों का प्रदर्शन अक्सर निकाय चुनावों के परिणामों से मेल खाता रहा है. जो मोर्चा स्थानीय चुनावों में बढ़त बनाता है, वह उसी प्रवृत्ति को विधानसभा चुनाव तक ले जाता है और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है. यह पैटर्न कई चुनाव चक्रों में देखा गया है. पंचायत, नगरपालिका और निगम स्तर पर जनता का फैसला अक्सर विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक मूड का संकेत देता है.

एनडीए के लिए पहचान बढ़ाने का मौका

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए यह चुनाव राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर माना जा रहा है. अभी तक गठबंधन वोट शेयर को सीटों में बदलने में सफल नहीं रहा है. हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में सुरेश गोपी की त्रिशूर से जीत ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और त्रिकोणीय मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.

बंगाल में लागू होगा यूपी वाला मॉडल

कोलकाता. उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में इस मॉडल को लागू किया था लेकिन अब चुनाव आयोग ने वहां से सीख लेकर पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने का फैसला किया है.

इस मॉडल के तहत बुर्के वाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर भी की जाएगी. ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जांच दो बार या उससे ज्यादा बार भी हो सकती है. समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पुलिस ने मतदान केंद्र से बहुत पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे और बुर्के वाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर ही की जा रही थी. इतनी जगह बैरिकेड लगाए गए थे और इतनी जांच हो रही थी कि बहुत से लोग रास्ते से लौट गए.

बहरहाल, नियम यह कहता है कि बुर्के वाली महिला को मतदान केंद्र के भीतर जाकर ही अपना चेहरा दिखाना है. वही पर मतदाता सूची में लगी फोटो से उसका मिलान होगा और वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगाई जाएगी.

बंगाल का रण : पुराने प्रतिद्वंद्वी और नई जंग

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर छिड़े संग्राम के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगीं या फिर घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को कमल खिलाने का मौका मिलेगा. इस चुनाव में चेहरे पुराने हैं और जंग नई है. यहां हम पश्चिम बंगाल की राजनीति के उन चमकते चेहरों की बात करेंगे जो अपने विरोधियों को जबरदस्त टक्कर देते नजर आ रहे हैं.

ममता बनर्जी- तीन बार बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकीं ममता बनर्जी राजनीति में एक अनोखी जगह रखती हैं. वे एक ही समय पर राज्य का शासन भी चलाती हैं और उसकी सबसे मुखर विपक्षी आवाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं. चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) और केंद्रीय फंड में हो रही कटौती को लेकर फैली बेचैनी ने बंगाल में राजनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे समय में ममता बनर्जी सहज रूप से एक बार फिर से एक जुझारू स्ट्रीट फाइटर की भूमिका में लौट आई हैं. इस रवैये ने उन्हें उस स्वाभाविक सत्ता-विरोधी लहर की धार को कुंद करने में मदद की है, जो अक्सर एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद सरकारों को परेशान करती है. उन्होंने एसआईआर की लड़ाई को बंगाल की सड़कों पर, नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा है. यह रणनीति एक ऐसे राजनेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करती है, जो टकराव की स्थितियों में और भी ज्यादा निखरकर सामने आती हैं.

अभिषेक बनर्जी- तृणमूल कांग्रेस के भीतर उनका उभार अब राजनीतिक विरासत के सवाल से कहीं आगे निकल चुका है. पिछले कुछ वर्षों में वे पार्टी के सबसे प्रभावशाली आयोजकों और रणनीतिकारों में से एक बनकर उभरे हैं, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें सेनापति अभिषेक का उपनाम मिला है. 38 साल की उम्र में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है.

सुवेंदु अधिकारी- बंगाल की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिकाओं को इतनी शिद्दत से निभाया हो, जितना कि सुवेंदु अधिकारी ने. जमीनी स्तर के आंदोलनकारी से लेकर कैबिनेट मंत्री और अब बंगाल में विपक्ष के नेता तक अधिकारी का राजनीतिक सफर राज्य की बदलती राजनीतिक धारा का ही एक आईना रहा है. अधिकारी परिवार का रूपनारायण नदी के किनारे कोलाघाट से लेकर रामगढ़ तक फैले राजनीतिक क्षेत्र पर लंबे समय से दबदबा रहा है. यह एक ऐसा गढ़ है जिसे उन्होंने चार दशकों से भी अधिक समय तक सींचा है.

विशेष | नीतीश का सम्मान या सियासी रणनीति, क्या है प्लान 2030?

अनंत सिंह क्यों छोड़ रहे राजनीति

पटना. बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी अगली पीढ़ी राजनीति में कदम रखेगी. राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह ने यह घोषणा की और फिर वापस जेल चले गए. उनके इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

अनंत सिंह के करीबी बताते हैं कि वे नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और हमेशा उनके मार्ग पर चलते रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है और

वे जिस भी परिवार के सदस्य को मैदान में उतारेंगे, जनता उनका समर्थन करेगी. दरअसल, 64 वर्षीय अनंत सिंह पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और सजा की आशंका भी बनी हुई है. ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वे अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए अपने बेटों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं. मोकामा में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए यह फैसला एक सियासी चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

हमेशा वफादार कहलाते रहेंगे अनंत सिंह!- दरअसल, अनंत सिंह पहले भी कई बार कह चुके थे कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वे सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेंगे. उस समय इसे सामान्य राजनीतिक बयान माना गया था. लेकिन अब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जा रहे हैं, उसी समय अनंत सिंह ने अब आगे अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी. ऐसे में इसे कई लोग उनके उस पुराने बयान को निभाने और खुद को नीतीश कुमार का वफादार साबित करने के रूप में देख रहे हैं. राजनीति के जानकारों का मानना है यह कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि इससे उन्होंने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है.

अगली पीढ़ी के लिए राजनीति का रास्ता साफ- अनंत सिंह का यह बयान उनकी पारिवारिक राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि अब उनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में आगे आएंगे. मोकामा क्षेत्र में लंबे समय से उनकी मजबूत पकड़ रही है. ऐसे में राजनीति से औपचारिक दूरी बनाकर उन्होंने अपने परिवार की अगली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ कर दिया है.

नीतीश कुमार और अनंत सिंह का अनोखा संबंध

नीतीश कुमार और अनंत सिंह का राजनीतिक रिश्ता 'सत्ता की मजबूरी' और 'बाहुबल' के तालमेल का उदाहरण रहा है. इस रिश्ते की शुरुआत 2005 में हुई, जब नीतीश कुमार ने मोकामा के इस बाहुबली को जेडीयू में शामिल कर टिकट दिया और अनंत सिंह ने जीत के बाद कथित तौर पर नीतीश को सिक्कों से तौला था. साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी.इसके बाद वे निर्दलीय और फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2024-25 के आसपास यह कड़वाहट फिर से नजदीकी में बदलती दिखी.